

पहले मुख्य समाचार।

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ऊर्जा और हथकरघा विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उपभोक्ताओं के बिजली मीटर से जुड़ी शिकायतों के गहन जांच के दिये निर्देश। बुनकरों की आय, सम्मान और स्थायित्व को बताया सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक वीडियो में विधायी निकायों में महिला आरक्षण की महत्ता पर की बात। कहा- महिलाओं के लिए आरक्षण से अधिक जीवंत तथा सहभागी बनेगा लोकतंत्र।
- विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआईआर अभियान के तहत आज होने जा रहा है अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन। सभी जिलों में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जानकारी साझा करेंगे जिला निर्वाचन अधिकारी।
- जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में देश में शीर्ष स्थान पर है उत्तर प्रदेश।

\*\*\*\*\*

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा की और बिजली मीटर के संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए इसकी गहन जांच के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट-

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में किए गये सुधारों का वास्तविक लाभ अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचे, इसके लिए विश्वसनीय आपूर्ति, तकनीकी दक्षता और जवाबदेही को आधार बनाकर कार्य किया जाए। श्री योगी ने कहा कि आम उपभोक्ता स्वभाविक रूप से इमानदार होता है। यदि उसे समय पर सही बिल प्राप्त हो जाए तो वह भुगतान करने में कोई हिचक नहीं करता। उन्होंने निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का समुचित और समयबद्ध समाधान किया जाए, ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में सभी तापीय इकाइयों को पूर्ण क्षमता के साथ संचालित रखा जाए और ग्रीष्मकालीन मांग के दृष्टिगत आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जाए। समाचार कक्ष से अरुण।

\*\*\*\*\*

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में हथकरघा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि बुनकर केवल परंपरा के संवाहक नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सशक्त आधार हैं। उनकी आय, सम्मान और आजीविका की स्थिरता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। मुख्यमंत्री ने बुनकरों के लिए परिणाम उन्मुख और क्लस्टर-आधारित नई कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट-

मुख्यमंत्री ने कहा कि बुनकरों को तकनीक, डिजाइन, पैकेजिंग और बाजार तक पहुंच एक ही ढांचे में सुनिश्चित हो। उन्होंने बुनकरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर विशेष जोर दिया। श्री योगी ने अधिकारियों को सौर ऊर्जा से संचालित पावरलूम को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए। बैठक के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लगभग 2 लाख बुनकर राज्य की अर्थव्यवस्था के सशक्त आधार व स्वावलंबन की कहानी हैं। इनका सम्मानजनक जीवन सरकार की प्राथमिकता है। समाचार कक्ष से प्रेम चन्द्र गुप्ता।

\*\*\*\*\*

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण समय की मांग है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण से लोकतंत्र और अधिक जीवंत तथा सहभागी बनेगा। एक वीडियो में समाचार पत्रों में दिए गए अपने विशेष लेख का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा और उसे पारित कराने के लिए 16 अप्रैल को संसद का सत्र बुलाया गया है।

एक बहुत ही सकारात्मक माहौल दिख रहा है। मैंने अखबारों में एक लेख लिखा है। आप इस लेख को जरूर पढ़ें, औरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें और सभी राजनीतिक दलों को प्रेरित करें और उनका उत्साहवर्धन करें की वह उमंग के साथ 16, 17, 18 संसद में इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं, तो इसको पारित करें और सब मिलकर इसका जश्न मनाएं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जरूरी है कि 2029 के लोकसभा चुनाव तथा आने वाले समय में विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान के साथ आयोजित हों।

हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था। और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब हमारे देश के नारी शक्ति को जनप्रतिनिधियों के रूप में लोकसभा में विधानसभाओं में 33 प्रतिशत स्थान मिलना ही चाहिए।

विधायिका में महिला आरक्षण की पहल पर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय जनक नंदिनी निषाद ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार जताया।

**इसको हम बहुत ही अच्छे और बहुत ही अपने दिल से आभार व्यक्त करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। 33 प्रतिशत नारी बंधन योजना के तहत 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए इसके लिए दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद।**

\*\*\*\*\*

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कल गाजियाबाद के नितरा में आयोजित 'नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इनोवेशन इन प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल' कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने न्यू एज फाइबर से बने प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स के विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन किया। केंद्रीय मंत्री ने ओक और मिल्क वीड की खेती का भी निरीक्षण किया। अपने सम्बोधन में केंद्रीय मंत्री श्री सिंह ने टेक्सटाइल के क्षेत्र में एआई की महत्ता पर विशेष जोर दिया।

**एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोग कहेंगे टच टाइम में क्या काम है? हैंडलूम से लेकर के सिंथेटिक तक प्रोडक्शन से लेकर के उसके ट्रेसिबिलिटी तक एआई और ब्लॉक चैन का इसमें जरूरत पड़ेगा। तो हम इस दिशा में भी आगे काम करेंगे।**

\*\*\*\*\*

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल वाराणसी में खुशीपुर स्थित समेकित क्षेत्रीय केंद्र-सीआरसी के अस्थायी भवन एवं 'क्रॉस डिसेबिलिटी शीघ्र हस्तक्षेप' केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगजन और वरिष्ठजनों के सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

\*\*\*\*\*

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआईआर अभियान के तहत आज प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इसी के साथ पांच माह से चल रहा एसआईआर अभियान भी समाप्त हो जाएगा। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटे हैं और नये मतदाताओं के नाम भी जोड़े गये हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा आज मतदाता सूची के अंतिम वास्तविक आंकड़ों की लखनऊ में घोषणा करेंगे। इसके बाद सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करने के साथ ही राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में बढ़े हुए नये मतदाताओं और सूची से हटाये गये मतदाताओं की जानकारी साझा की जाएगी।

\*\*\*\*\*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि केन्द्र सरकार देश में घरेलू एलपीजी की सौ प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है।

**एलपीजी सप्लाई प्रेजेंट जियो पोलिटिकल सिचुएशन में इफेक्ट हुई है और हमारे लगभग 60: ऑफ रिक्वायरमेंट है कंट्री का एलपीजी का वह इंपोर्ट से होता है इसके चलते डोमेस्टिक कंज्यूमर को प्रायोटाइज किया गया और घरेलू यूज के लिए एलजी की सप्लाई 100: एंशोर की गई है हमारे किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई झ्रई आउट रिपोर्टड नहीं है।**

औषधि विभाग के संयुक्त सचिव सत्यप्रकाश टी.एल. ने पश्चिम एशिया संकट के बीच कल नई दिल्ली में कहा कि सरकार ने औषधि उद्योग को सहायता देने और आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए 40 पेट्रो रसायन उत्पादों पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया है।

\*\*\*\*\*

प्रदेश ने वित्त वर्ष दो हजार पचीस-छब्बीस में जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद में अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। राज्य ने इस अवधि में जेम पोर्टल पर बाइस हजार तीन सौ सैंतीस करोड़ रुपये की खरीद की। भारत सरकार ने प्रदेश की जेम खरीद नीति की सराहना करते हुए राज्य को पारदर्शी खरीद के क्षेत्र में एक आदर्श घोषित किया है।

\*\*\*\*\*